कृपया प्रकाशनार्थ **6 अगस्त 2012**

इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन के अध्यक्ष डा.शरदचंद्र गोखले तथा पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक द्ववारा मुंबई में 6 अगस्त को संयुक्त पत्रकार परिषद में प्रसारित वक्तव्य

कुष्ठपीडितों को मानवाधिकार दिलाने के लिए समिति का गठन

मुंबई, सोमवार : कुष्ठपीडितों को मानवाधिकारों का संरक्षण हो तथा वह दिलाने के प्रयास संगठित ढंग से सही दिशा में हो इसलिए 'कुष्ठपीडित मानवाधिकार सुरक्षा समिति' की स्थापना करने का निर्णय इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन ने किया है. इस समिति के अध्यक्ष के रुप में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक को मनोनित किया है, तो समिति के उपाध्यक्ष का दायित्व इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन के अध्यक्ष डा.शरदचंद्र गोखले को सौंपा गया है. डा.शरदचंद्र गोखले ने मुंबई में संयुक्त पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी. श्री.राम नाईक भी इस समय उपस्थित थे.

इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए डा.शरदचंद्र गोखले ने कहा,''कुष्ठपीडितों के लिए काम करते समय हमें बार-बार यह अनुभव होता है कि कई बार उनके मानवाधिकार का ही हनन होता है. पिछले कुछ महीनों में इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन के माध्यम से हमने राष्ट्रीय तथा विभिन्न राज्यों के मानवाधिकार आयोगों के पास कुष्ठपीडितों की कुल 151 शिकायते दर्ज की. उनमें से 93 मामलों का सकारात्मक निर्णय हुआ, तो 40 मामलों में अभी भी निर्णय बाकी है. इस परिस्थिती का विचार करने के बाद हमे लगता है कि मानवाधिकार हनन के मामलों में से 75 से 80 प्रतिशत मामलों में मानवाधिकार आयोग के पास जाने से कुष्ठपीडितों को न्याय मिल सकता है. इसी विचार से हमने समिति बनाने का निर्णय किया है. श्री.राम नाईक इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे और कुष्ठपीडितों के नैशनल फोरम के अध्यक्ष पद्मश्री डा.पी.के.गोपाल समिति के कार्याध्यक्ष रहेंगे. राजस्थान के श्री.सुरेश कौल को समिति के सचिव की जिम्मेदारी सौपी गयी है. जिन 19 राज्यों में कुष्ठपीडित है उन सभी राज्यों में से एक-एक प्रतिनिधी को इस समिति पर संयोजक बनाये जाएंगे. महाराष्ट्र का प्रतिनिधीत्व पूर्व महासंचालक (कारागृह) श्री. राम बेलवडी करेंगे. अन्य संयोजकों में दिल्ली के डा.सी.एस.वॉल्टर, आंध्रप्रदेश के डा.रंगनाधन राव, तामिलनाडु के डा.नुरुद्दीन है. अन्य राज्यों के प्रतिनिधी तय करने की प्रकिया जारी है.''

..2..

इस समिति की अध्यक्षता की स्वीकृति के निर्णय तक कैसे पहुँचे यह बताते हुए श्री.राम नाईक ने कहा,''पिछले कई वर्षों से मैं भी कुष्ठपीडितों की समस्याएं सुलझाने के प्रयत्न कर रहा हुँ. कुष्ठपीडितों के सबलिकरण के लिए राज्यसभा में 2007 में याचिका दर्ज की थी. इस याचिका की रपट पर अमल हो इसलिए लगातार कोशिश जारी है. इसलिए दो बार पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील से भी हमारे प्रतिनिधी मंडल ने गत वर्ष में दो बार चर्चा की. महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री से बार-बार विचारविमर्श किया. इन चर्चाओं में से कुछ समस्याएं हल निकालने के रास्ते पर है लेकिन मोटे तौर पर तो केंद्र तथा राज्य सरकारों का कुष्ठपीडितों की ओर संवेदनाहीन रवैयाही नजर आता है. हमारी कोशिशें तो जारी रहेगी, साथ ही मानवाधिकारों का संरक्षण भी कुष्ठपीडितों को देने का प्रयास रहेगा. यह प्रयास अगर संगठन के जरिए करें तो वह अधिक प्रभावी होगा, इस भूमिका में मैंने इस समिती के अध्यक्षपद का दायित्व स्वीकार किया है.''

आनेवाले तीन महिनों में सभी राज्यों के मानवाधिकार सुरक्षा समिति के संयोजक प्रतिनिधी निश्चित किए जाएंगे. देश के सभी कुष्ठपीडितों के मानवाधिकार हनन के मामले समिति के पुणे स्थित मुख्यालय में भेजे जाएं ऐसी अपील भी श्री.राम नाईक व डा.शरदचंद्र गोखले ने की है. **पता:** इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन-हेल्थ अलायन्स, कास्प भवन, सर्वे क्र.132/2, फ्लॉट क्र.3, पाषण-बाणेर लिंक रास्ता, पुणे 411021, टेलिफैक्सः020-25862836, ई-मेलः ilupune@gmail.com

(कार्यालय मंत्री) के लिए